भारत का संघ और अन्य

बनाम

असम राज्य

10 सितंबर, 2004

[न्यायाधिपति अरिजीत पासायत और न्यायाधिपति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर]

रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1966--धारा 3 और 8-अधिनियम के तहत अपराध-जमानत-धारित: जमानत देना बल के अधिकारी को वैधानिक रूप से प्रदान किए गए विवेक पर निर्भर है और सामग्री की पर्याप्तता के संबंध में राय बनाने के नुस्खे द्वारा नियंत्रित किया जाता है या अन्यथा-अधिनियम के तहत सभी अपराध-जमानती नहीं हैं-इसके अलावा, चूंकि अधिनियम के तहत अपराधों में पांच साल तक की कैद का प्रावधान है, इसलिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुसूची I के भाग II के आवेदन के अनुसार, वे गैर-जमानती हैं।

रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम 1966 की धारा 8 की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी के रुख को स्वीकार कर लिया कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों को विशेष रूप से जमानती बनाया गया है और केवल तभी जब आरोपी किसी अपराध में न हो।

सुरक्षा/ज़मानत प्रदान करने के लिए उसे अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है। इस फैसले के खिलाफ समीक्षा को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ता-भारत संघ ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के प्रावधान के प्रभाव को उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए माना-

1. रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1966 की धारा 8(2) के परंतुक के खंड (ए) ने अधिकारी को राय बनाने के लिए दो विकल्प दिए हैं यानी कि क्या इसके खिलाफ संदेह का पर्याप्त सबूत या उचित आधार है। अभियुक्त व्यक्ति यह कहीं भी अभियुक्त के जमानत पाने के अधिकार से संबंधित नहीं है। परन्तुक के खण्ड (बी) द्वारा तीसरी श्रेणी पर विचार किया गया है। यह श्रेणी ऐसे मामले से संबंधित है जहां पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है। ऐसे मामले में संबंधित अधिकारी को आरोपी व्यक्ति को उसके निष्पादन बांड पर रिहा करने की शक्ति है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि अधिनियम के तहत सभी अपराध जमानती हैं।ऐसा दृष्टिकोण अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधानों के विपरीत है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुसूची I में अपराधों को वर्गीकृत किया गया है। भाग I भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से संबंधित है

और भाग II 'अन्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों के वर्गीकरण' से संबंधित है। निर्विवाद रूप से वर्तमान मामला भाग II के अंतर्गत आता है। 3 साल और उससे अधिक लेकिन 7 साल से अधिक की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए निर्धारित सजा के आधार पर अपराधों को वर्गीकृत करते समय, यह प्रावधान किया गया है कि अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। [327-ई, एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 608/1999

सीआरएल विविध सी संख्या 219/95 में सीआरएल ओ आवेदन संख्या 620 1995 में असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.6.96 से।

श्रीमती किरण भारद्वाज, एस. एन. टेरडोल और सुश्री सुषमा सूरी अपीलार्थी के लिए।

सुश्री कृष्णा शर्मा, वी. के. सिद्धार्थन और नीरज कुमार उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति अरिजीत पासायत :

यह एक दिलचस्प मुकदमा है जहां यूनियन ऑफ इंडिया ने असम राज्य द्वारा अपनाए गए रुख पर सवाल उठाया है। राज्य की अपील को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर

लिया। विवाद बहुत ही संकीर्ण दायरे में है। मुद्दा यह है कि क्या रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम 1966 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधानों के तहत विचार किए गए अपराधों के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 438 के तहत एक आवेदन दायर किया जा सकता है।) एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख करने के बाद माना कि अपराध जमानती थे। इस आधार पर उपयुक्त संशोधन के लिए एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया था कि अधिनियम की धारा 8 का उचित विश्लेषण नहीं किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसे राज्य बनाम सुंदरा पांडियन (1979) सीआरएल लॉ जर्नल एनओसी 194 में संक्षेप में बताया गया था। समीक्षा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था और मूल रूप से व्यक्त दृष्टिकोण सही था

अपील के समर्थन में भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 8 में निहित प्रावधानों को उचित परिप्रेक्ष्य में ध्यान में नहीं रखा है। उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया है कि आरोपी को जमानत पाने का अधिकार है, बशर्ते वह जमानत/सुरक्षा देने को तैयार हो। यह माना गया कि जब अभियुक्त सुरक्षा या जमानत देने की स्थिति में न हो तभी उसे अधिकार क्षेत्र वाले

मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 8 की उप-धारा (2) के प्रावधान के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।

असम राज्य के विद्वान वकील ने सीआरएल मूल आवेदन संख्या 620/1995 और सीआरएल विविध मामले संख्या 219/95 में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का समर्थन किया।

विवाद अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधानों के आसपास घूमता है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"8. गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ कैसे की जाए - (1) कब किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए बल के एक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या धारा 7 के तहत उसे भेजा जाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए बल का अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उन्हीं प्रावधानों के अधीन होगा जैसा कि एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्रयोग कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन है किसी संज्ञेय मामले की जांच करते समय:

उसे उपलब्ध कराया -

(ए) यदि बल के अधिकारी की राय है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है, तो वह या तो उसे मामले में अधिकार

क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत दे देगा या उसे हिरासत में भेज देगा। ऐसा मजिस्ट्रेट;

(बी) यदि बल के अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो वह आरोपी व्यक्ति को जमानत के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, जैसा कि बल का अधिकारी कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देगा और मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा।

एक जमानती अपराध को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 2(डी) के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 8 की उपधारा (2) के परंतुक को पढ़ने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि तीन स्थितियों की परिकल्पना की गई है। तीन में से दो स्थितियाँ परंतुक के खंड (ए) से संबंधित हैं। यदि बल के अधिकारी की राय है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है तो वह (ए) या तो उसे मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत दे देगा या (बी) ऐसे मजिस्ट्रेट को हिरासत में लेने के लिए भेज देगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया है कि मामले के अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी द्वारा जो निर्देश दिया जा सकता है वह आरोपी के जमानत पाने के अधिकार का परिणाम है।

व्याख्या स्पष्ट रूप से ग़लत है. यह देखा गया है कि यह जमानती है या नहीं, इसका निर्णय अधिकारी के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह दृष्टिकोण परंतुक की स्पष्ट भाषा को नजरअंदाज करता है और विवेक का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। इस तरह के विवेक का प्रयोग सामग्री की पर्याप्तता या अन्यथा के संबंध में राय बनाने के नुस्खे द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है

इस विवाद को दूसरे नजरिये से भी देखा जा सकता है. संहिता की अनुसूची I में अपराधों को वर्गीकृत किया गया है। भाग I भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से संबंधित है और भाग II "अन्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों के वर्गीकरण" से संबंधित है। निर्विवाद रूप से वर्तमान मामला भाग II द्वारा कवर किया गया है, जबकि 3 साल और उससे अधिक लेकिन 7 साल से अधिक नहीं के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए निर्धारित दंड के आधार पर अपराधों को वर्गीकृत करते हुए, यह प्रावधान किया गया है कि अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। हालांकि, अधिनियम की धारा 5 द्वारा एक अपवाद बनाया गया है, जिससे अपराध गैर-संज्ञेय हो गया है। उस अपवाद को छोड़कर, संहिता की अनुसूची I अधिनियम की धारा 3 के तहत लागू होती है, पहले अपराध के लिए कारावास पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और बाद के अपराधों के लिए भी समान अवधि तय की जाती है। केवल विशेष और पर्याप्त कारणों को

दर्ज करने के लिए न्यूनतम कारावास हो सकता है। क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष।

राय बनाने के लिए अधिकारी को दो विकल्प दिए जाते हैं यानी कि क्या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है। यह कहीं भी आरोपी को जमानत पाने के अधिकार से संबंधित नहीं है। तीसरी श्रेणी पर प्रावधान के खंड (बी) द्वारा विचार किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि जब अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पर्याप्त सबूत या उचित संदेह नहीं है, तो वह आरोपी व्यक्ति को जमानत के साथ या उसके बिना बांड भरने पर रिहा कर देगा जैसा कि बल का अधिकारी उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है यदि और जब ऐसा हो क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आवश्यक है और वह मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। यह श्रेणी ऐसे मामले से संबंधित है जहां पर्याप्त सबूत या संदेह के उचित आधार का अभाव है। ऐसे मामले में संबंधित अधिकारी को आरोपी व्यक्ति को उसके निष्पादन बांड पर रिहा करने की शक्ति है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि अधिनियम के तहत सभी अपराध जमानती हैं। ऐसा दृष्टिकोण अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधानों के विपरीत है।

इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना उचित नहीं था कि चूंकि अपराधों को अधिनियम के तहत विशेष रूप से जमानती बनाया गया है, इसलिए वे जमानती हैं। निष्कर्ष अनिश्चित है. ऐसा होने पर, हमने

सीआरएल मूल आवेदन संख्या 620/1995 और सीआरएल विविध मामले संख्या 219/95 दिनांक 27.6.96 में एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया।

अपील की अनुमति है।

वी एस एस

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।